announced measures for rationalisation, quality control and growth of drugs and pharmaceutical industry. The measures do not in any way favour the multinational.

Drugs manufactured by different producers

950. SHRl AJIT P. K.. JOGI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several drugs are being produced in the country by more than one producer;

\b) if so, what are the names of those drugs;

(c) whether it is also a fact that there arc multiplicity of prices due to different cost of production of each producer, due to technology difference, locational and rther factors;

(d) if so. what was the cost of production of each producer;

(e) whether it is also a fact that three options of return have been guaranteed to the producer of times under DPCO, 19X7; and

(f) if so. how the average price will be fixed in the absence erf Drug Prices Equalisation Account ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) Yes. Sir.

(b) My Ministry monitors the production of 87 bulk drugs. Names of these drugs are published in the performance Budget of this Ministry, copies of which have been laid on the Table of the House. Most of these drugs are produced by several producers.

(c) Yes. Sir.

(d) Since the number of producers for (he 87 bulk drugs are numerous, time and labour involved in collection and compilation of cost of production in respect of eaeli of them will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(e) Yes, Sir.

(f) A weighted average price for a hulk drug will be fixed taking into account the different prices fixed for different manufacturers in respect of that bulk drug on the basis of options exercised by them.

एच. बी. जे. पाइपलाइन

951. **श्री रशीद मसूद** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच.बी.जे. पाइपलाइन के प्रथम चरण का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है और इस परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाला कच्चा माल उपयुक्त उपयोग के अभाव में बिना इस्तेमाल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस कच्चे माल का उपयुक्त उपयोग करने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने क्या भावी कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारr«?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) हजीरा से विजयपुर तक एच. बी. जे. पाइपलाइन का पहला चरण अगस्त, 1987 में चालू कर दिया गया है। और इसने विजयपुर में एन एफ एल के उर्वरक संयंत्र को प्राकृतिक गैस की सप्लाई आरम्भ कर दी है। इस संयंत्र द्वारा ली जाने वाली गैस 0.2 एम एम सी एम डी से बढ़कर 0.5 एम एम सी एम डी हो गई है और धीरे-धीरे बढ़कर 1987 के अन्त तक यह 1.65 एम एम सी एम डी हो जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोबर से ऊर्जा प्राप्त किया जाना

952. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गोबर से प्राप्त ऊर्जा का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो क्या यह भी पता लगाया गया है कि इसका 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर दिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार इसको उचित ढंग से और उचित समय पर प्रयोग किए जाने की व्यवस्था करेगी और यदि हां, तो इस प्रयोजन

के लिए क्या योजना बनाई गई है और उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) (क) यह अनुमान लगाया गया है कि देश में वर्षभर में करीब 980 मिलियन टन गोबर उपलब्ध होता है और इसका अधिकांश भाग अर्थात् 1/3 भाग से लेकर 1/2 भाग तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

(ख) भारत सरकार ईंधन तथा उर्वरक के लिए गोबर का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से सन् 1981-82 से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन पी बी डी) को कार्यान्वित कर रही है । 177 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से सातवीं योजना अवधि में 5.5 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया गया । बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन पी बी डी) को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों ने नोडल विभागों की स्थापना की है तथा कुछ राज्यों ने राज्य एजेन्सियों की भी स्थापना की है । इसके अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा स्वयंसेवी एजेन्सियां भी इस कार्य में शामिल हैं ।

बेरोजगार स्नातकों को पैट्रोलियम और एल. पी. जी. एजेन्सियों का दिया जाना

953. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पैट्रोलियम और एल. पी. जी. एजेंसियों के लिए कितने-कितने लाइसेंस बेरोजगार स्नातकों को दिए गये हैं; और

(ख) क्या सरकार यह पता लगाने के लिए कोई जांच कराने का विचार रखती है कि ये सभी लाइसेंस उन्हीं व्यक्तियों को दिए गए हैं जो पहले से ही इस व्यापार में लगे हुए हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) जी, नहीं । वर्तमान नीति संबंधी दिशा निर्देशों में इस बात की व्यवस्था है कि यदि किसी व्यक्ति/सहकारी समिति के पास पहले से ही किसी कम्पनी की एल पी जी/केरोसीन/एच डी ओ/एच एस डी/एम एस/लुब्रीकेटिंग तेलों की डीलरशिप/वितरणशिप है तो उस व्यक्ति/सहकारी समिति को नई डीलरशिप/वितरणशिप नहीं दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1984–85			1985–86			1986–87		
		एलपीजी	आरओ	एसकेओ एलडीओ	एलपीजी	आरओ	एसकेओ एलडीओ	एलपीजी	आरओ	एसकेओ एलडीओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	9	10	7	10	6	4	6	7	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	5	—	3	5	3	1	—	2	4
4.	बिहार	4	11	3	7	17	1	—	7	4
5.	गुजरात	4	8	4	9	11	10	3	3	6
6.	हरियाणा	2	2	1	4	4	—	1	3	1
7.	हिमाचल प्रदेश	2	1	—	1	—	—	—	3	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	5	1	—	—	4	3
9.	कर्नाटक	5	10	2	8	8	—	7	7	—
10.	केरल	7	2	—	10	7	—	9	4	—
11.	मध्य प्रदेश	10	6	7	6	11	5	2	1	1
12.	महाराष्ट्र	13	16	8	24	12	10	10	9	5
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	मणिपुर	—	—	—	1	3	2	—	—	—
15.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—